



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 525]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2009/भाद्र 20, 1931

No. 525]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2009/BHADRA 20, 1931

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2009

सं. 101/2009-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 667(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, इससे उपाबद्ध सारणी में विनिर्दिष्ट माल को,—

(i) सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमा-शुल्क से, और;

(ii) उक्त सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है।

2. इस अधिसूचना के तहत छूट निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी, अर्थात् :—

(1) यह कि माल का आयात इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों, आधारभूत रसायनों एवं फार्मास्यूटिकल्स, कपड़ों एवं वस्त्रों, प्लास्टिक, हस्तशिल्प, रसायनों एवं संबद्ध उत्पादों और लेदर तथा लेदर के उत्पादों के निर्यात के लिए किया गया है और ये उनसे अलग हैं, जिनकी सीमा-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के निम्नलिखित अध्यायों/शीर्षकों के अंतर्गत शामिल उत्पादों के निर्यात के लिए आवश्यकता होती है, नामशः :—

अध्याय 1 से 4, 5 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 6 से 24, 25 से 27, 31, 40, 43, 44 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 45, 47 से 49, 68 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 69, 70, 71, 89, 93, 97 (हस्तशिल्प को छोड़कर), 98; शीर्षक 7201 से 7212, 7218 से 7220, 7224 से 7226, 7401 से 7406, 7501 से 7504, 7601 से 7603, 7801 से 7802, 7901 से 7903, 8001 से 8002, प्राथमिक एवं मध्यवर्ती स्वरूप में अध्याय 81 की धातुएं तथा 8401 ।

(2) यह कि आयातित माल, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ईपीसीजी) योजना के तहत सामान्य सेवा प्रदाता को (जिसे इसके बाद सीएसपी कहा गया है) विदेश व्यापार महानिदेशक (जिसे इसके बाद डीजीएफटी कहा गया है), वाणिज्य विभाग (जिसे इसके बाद डीओसी कहा गया है), अथवा राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा विदेश व्यापार नीति के अध्याय 5 के निबंधनों के अंतर्गत निर्यात उत्कृष्ट कस्बों (जिसे इसके बाद टीईई कहा गया है) में जारी वैध प्राधिकार से कवर हों, जिसमें माल को शून्य सीमाशुल्क पर आयात की अनुमति दी गयी हो और कथित प्राधिकार को निकासी के समय समुचित सीमाशुल्क अधिकारी के समक्ष नामे करने के लिए प्रस्तुत किया जाए:

शर्त यह है कि कथित सारणी के क्रम सं.4 पर विनिर्दिष्ट खुले पुर्जों के आयात के लिए, प्राधिकार की वैधता अवधि पूरी निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए अनुमत अवधि मानी जाएगी :

(3) यह कि इस योजना के अंतर्गत जारी प्राधिकार में कथित पूंजीगत माल के प्रयोक्ताओं के ब्यौरे और निर्यात बाध्यता (जिसे इसके बाद ई ओ कहा गया है) की मात्रा के ब्यौरे होंगे, जिसे प्रत्येक प्रयोक्ता पूरी करेगा ।

(4) यह कि सामान्य सेवा प्रदाता या विनिर्दिष्ट प्रयोक्ताओं में से कोई भी वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रचालित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टी यू एफ एस) के तहत फिलहाल कोई लाभ नहीं ले रहा है।

(5) यह कि सामान्य सेवा प्रदाता या विनिर्दिष्ट प्रयोक्ताओं में से कोई भी माल आयात किए जाने के वर्ष में, विदेश व्यापार नीति के पैरा 3.16 के अंतर्गत हैसियत धारक प्रोत्साहन योजना का लाभ नहीं ले रहा है।

(6) यह कि निर्यात की बाध्यताएं पूरी होने तक आयातित माल को बिक्री/पट्टे या किसी और तरीके, से निस्तारित या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा ।

(7) यह कि सामान्य सेवा प्रदाता और प्रत्येक विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता लाइसेंस या प्राधिकार जारी होने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि के भीतर सीमा शुल्क उपायुक्त एवं सहायक सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा यथा विनिर्दिष्ट ऐसे प्रपत्र पर और ऐसी धनराशि का बांड भरेगा जो उसे एफ ओ बी आधार पर प्राधिकार में विनिर्दिष्ट आयातित माल पर बचाए गए शुल्क के 6 गुने के बराबर या ऐसी अधिक धनराशि जो हैंडबुक क्रियाविधि खंड-1 के पैरा 5.10 के निबंधनों के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी या क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा नियत या पृष्ठांकित किया जाए, निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए निम्निखित अनुपात में बाध्य करें, नामश:-

क्र. सं.	प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से अवधि	कुल निर्यात बाध्यता का अनुपात
(1)	(2)	(3)
1	पहले से चौथे वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत
2	पांचवें से छठे वर्ष का ब्लॉक	50 प्रतिशत

परन्तु यह कि जहां कोई रूग्ण इकाई औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अधिसूचित है अथवा जहां रूग्ण इकाई के संबंध में इसके पुनर्संजीवन के लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा कोई पुनर्वास स्कीम घोषित की जाती है, वहां निर्यात बाध्यता संचालक एजेंसी द्वारा तैयार और बी आई एफ आर/राज्य सरकार के पुनर्वास विभाग द्वारा अनुमोदित पुनर्वास पैकेज के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य अवधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी। जिन मामलों में पुनर्वास पैकेज में समयावधि विनिर्दिष्ट नहीं है उनमें निर्यात बाध्यता लाइसेंसिंग प्राधिकरण अथवा क्षेत्रीय प्राधिकरण द्वारा अनुमत्य समयावधि के अंतर्गत पूरी की जाएगी जो बारह वर्षों से अधिक नहीं होगी

यह भी प्रावधान किया गया कि वर्तमान संयंत्र और मशीनरी (ई पी सी जी के अंतर्गत अथवा अन्य रूप से पूर्व में आयातित) के लिए पूर्यों (पुनः मरम्मत/ तैयार किए गए पूर्यों सहित), ढांचों, रंगों, जुगतों, जुड़नारों, यंत्रों, प्रारम्भिक लाइनिंग के लिए प्रतिरक्षितों और प्रारम्भिक प्रभार के लिए उत्प्रेरकों को ई पी सी जी स्कीम के अंतर्गत इस शर्त के अधीन आयातित करने की अनुमति दी जाएगी कि ऊपर विहित सामान्य निर्यात बाध्यता के 50% के समतुल्य निर्यात बाध्यता प्राधिकार जारी होने की तिथि से 6 वर्षों में पूरी की जाएगी बशर्ते कि उक्त पूर्यों, आदि के आयात का सी आई एफ मूल्य ई पी सी जी प्राधिकार के अंतर्गत संयंत्र और मशीनरी के सी आई एफ मूल्य के 10% तक सीमित होगा अथवा ई पी सी जी स्कीम के अलावा अन्य रूप से पूर्व में आयातित संयंत्र और मशीनरी के बुक वैल्यू के 10% जैसा मामला हो, तक सीमित होगा।

परन्तु किसी विशिष्ट ब्लॉक वर्ष की निर्यात बाध्यता को पूर्ववर्ती ब्लॉक में किए गए अधिक निर्यातों के समक्ष मंजूर किया जा सकेगा;

(8) यह कि यदि आयातकर्ता सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 3 के अंतर्गत उद्ग्रहणीय अतिरिक्त शुल्क के संबंध में छूट का दावा नहीं करता है, तो उसे निर्यात बाध्यता के परिगणन के संबंध में बचाई गई शुल्क राशि के संगणन के प्रयोजनार्थ उक्त सीमा शुल्क से छूट प्राप्त करने संबंधी लाभ उठाने वाला नहीं समझा जाएगा बशर्ते अतिरिक्त शुल्क अदा करने का सेनवैट क्रेडिट न लिया गया हो;

(9) यह कि प्राधिकारधारी तथा अन्य विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता, प्राधिकार जारी किए जाने की तारीख से प्रत्येक ब्लॉक की समाप्ति से 30 दिन के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, सहायक सीमा शुल्क आयुक्त या उप सीमा शुल्क आयुक्त को समाधानप्रद रूप में पूरी की गई निर्यात बाध्यता का परिणाम दर्शित करने से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करता है और जहां किसी विशिष्ट ब्लॉक की निर्यात बाध्यता पूर्ववर्ती शर्त के निबंधनों के अनुसार पूरी नहीं की गई है, वहां आयातकर्ता, उक्त ब्लॉक की समाप्ति से तीन मास के भीतर उतनी रकम का, जो यदि

इसमें अंतर्विष्ट छूट न दी गई होती तो, माल पर उद्ग्रहणीय शुल्क के उस भाग के बराबर का जिसका वही अनुपात है जो निर्यात बाध्यता को पूरा न किया गए भाग का कुल निर्यात बाध्यता से है, माल की निकासी की तारीख से 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज की दर सहित संदाय करेगा;

(10) जहां प्राधिकारधारी शर्त (7) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता की अवधि की आधी अवधि में शर्त (7) में विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता का 75% या उससे अधिक पूरी करता है, उसकी शेष निर्यात बाध्यता माफ कर दी जाएगी और यह माना जाएगा कि उसने सारी निर्यात बाध्यताएं पूरी कर दी हैं।

(11) यह कि आयातित, समंजित या विनिर्मित पूंजी माल आयातकर्ता के कारखाने या परिसर में संस्थापित किए जाते हैं और अधिकारिता वाले यथा-स्थिति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क उप आयुक्त या सहायक उत्पाद शुल्क आयुक्त से आयातकर्ता के कारखाने या परिसरों में पूंजी माल के संस्थापन और उपयोग की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण-पत्र आयात पूरा होने की तारीख से छह मास से भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो उक्त सीमा शुल्क उपायुक्त या सहायक सीमा शुल्क आयुक्त अनुज्ञात करें, यथास्थिति प्रस्तुत किया जाता है:-

बशर्ते पुर्जों के आयात के मामले में, स्थापना प्रमाणपत्र आयात की तारीख से तीन वर्षों के भीतर प्रस्तुत करना होगा :

आगे शर्त यह है कि यदि आयातक केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से पंजीकृत नहीं है तो वह किसी स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा जारी संस्थापन और प्रयोग का उक्त प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर सकता है:

(12) यह कि आयात और निर्यात समुद्री बन्दरगाह-बेदी (रोजी-जामनगर सहित), चेन्नई, कोचीन, दहेज, धरमतर, हल्दिया (कोलकाता बन्दरगाह का हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स) काकीनाडा, कांडला, कोलकाता, कृष्णापटनम, मगडाल्ला, मंगलौर, मारमागोवा, मूलद्वारका, मुम्बई, मुन्धरा, नागापट्टिनम, न्हावा शेवा, ओखा, पारादीप, पिपाव, पोरबंदर, सिक्का, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम तथा वडिनार के माध्यम से अथवा अहमदाबाद, बंगलौर, भुवनेश्वर, चेन्नई, कोचीन, कोयम्बटूर, डाबोलिम (गोवा), दिल्ली, हैदराबाद, इन्दौर, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ (अमौसी), मुम्बई, नागपुर, राजासांसी (अमृतसर), श्रीनगर, त्रिवेन्द्रम तथा वाराणसी स्थित किसी विमानपत्तन के जरिए अथवा आगरा, अहमदाबाद, अनापार्थी (आंध्रप्रदेश), बाबरपुर, बंगलौर, भदोही, भटिन्डा, भीलवाड़ा, भिवाड़ी, भुसावल, छेहाड़ता (अमृतसर), कोयम्बटूर, दादरी, डाप्पर (डैरा बस्सी), दौलताबाद (वंजारवाड़ी तथा मालीवाड़ा),

दिल्ली, डिघी (पुणे), दुर्गापुर (निर्यात संवर्द्धन औद्योगिक पार्क), फरीदाबाद, गरही हरसारू, गौहाटी, गुंटूर, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, जमशेदपुर, जोधपुर, कानपुर, करूर, कोटा, कुंडली, लोनी (जिला गाजियाबाद), लुधियाना, मदुरै, मालनपुर, मन्डीदीप (जिला रायसेन), मिराज, मुरादाबाद, नागपुर, नासिक, पिम्परी (पुणे), पीतमपुर (इन्दौर), पांडिचेरी, रायपुर, रेवाड़ी, रुद्रपुर (नैनीताल), सलेम, सिंगानालूर, सूरत, सूरजपुर, तिरुपुर, तूतीकोरिन, उदयपुर, वड़ोदरा, वाराणसी, वालुज (औरंगाबाद) स्थित किसी इनलैंड कंटेनर डिपो के माध्यम से अथवा अगरतला, अमृतसर रेल कार्गो, अटारी रोड, चांगराबान्धा, डावकी, घोजाडंगा, हिल्ली, जोगबानी, महादीपुर, नेपालगंज रोड, नौतनवा (सौनौली), पेटरापोल, राणाघाट, रक्सौल, सिंघाबाद तथा सुतारखंडी भू-सीमा कस्टम स्टेशन के जरिए अथवा विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 4 के अंतर्गत अधिसूचित विशेष आर्थिक जोन के माध्यम से किए जाते हैं।

यह प्रावधान है कि सीमा शुल्क आयुक्त अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विशेष आदेश द्वारा अथवा सार्वजनिक नोटिस द्वारा और उनके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन किसी अन्य समुद्री बंदरगाह, विमानपत्तन, इनलैंड कंटेनर डिपो अथवा लैंड कस्टम स्टेशन के माध्यम से आयात और निर्यात की अनुमति प्रदान कर सकते हैं;

(13) उपर्युक्त शर्त (9) में कुछ भी अंतर्विष्ट हो, जहाँ लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी किसी भी ब्लॉक के लिए ब्लॉक क्रम में अवधि बढ़ाने अथवा दो वर्षों की अवधि तक निर्यात बाध्यता को पूरा करने की कुल अवधि अथवा निर्यात बाध्यता में कमी को नियमित करने के लिए अधिकतम ऐसी निर्यात बाध्यता के पाँच प्रतिशत तक, अवधि बढ़ाने की अनुमति प्रदान करता है वहाँ निर्यात बाध्यता की उक्त ब्लॉक क्रम में अवधि अथवा कुल अवधि को सीमा शुल्क के उपायुक्त अथवा सीमा शुल्क के सहायक आयुक्त, जैसा मामला हो, द्वारा बढ़ाया/माफ किया जा सकता है:

यह प्रावधान है कि शर्त (7) के प्रथम परन्तुक में उल्लिखित बीमार इकाईयों के संबंध में निर्यात बाध्यता की कुल अवधि को बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी:

आगे शर्त यह है कि निर्यात बाध्यता की अवधि, मूल निर्यात बाध्यता की 6 वर्ष की अवधि सहित 12 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जाएगी।

3. जहाँ उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट माल दोषपूर्ण अथवा इस्तेमाल के लिए अनुपयुक्त पाये जाते हैं तो उक्त माल को उनके आयात पर शुल्क के भुगतान की तिथि से तीन वर्षों के अंदर विदेशी आपूर्तिकर्ता को वापस पुनर्निर्यात किया जा सकता है।

यह प्रावधान है कि पुनर्निर्यात के समय सीमा शुल्क उपायुक्त अथवा सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, जैसा मामला हो, की संतुष्टि के लिए माल की आयात किए गए माल के रूप में पहचान की जाती है।

4. कथित सारणी के क्रम सं. 1 और 2 पर विनिर्दिष्ट माल के आयात के लिए, यह अधिसूचना 31 दिसंबर, 2011 से प्रभावी होगी।

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए-

1. 'पूंजीगत माल' का वही अर्थ है जो विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.12 में दिया गया है।

2. 'सामान्य सेवा प्रदाता (सीएसपी)' का अर्थ ऐसा सेवा प्रदाता है, जो डीजीएफटी, वाणिज्य विभाग अथवा राज्य औद्योगिक अवसंरचना निगम द्वारा किसी निर्यात उत्कृष्ट कस्बे में सामान्य सेवा प्रदाता के रूप में नामनिर्दिष्ट अथवा प्रमाणित है।

3. 'निर्यात बाध्यता'-

(1) का अर्थ है आयातक पर भारत से बाहर उत्पादित/उत्पादन के लिए सक्षम अथवा इस अधिसूचना के दृष्टिकोण से आयातित पूंजीगत माल के उपयोग द्वारा दी गई सेवा पर बाध्यता। निर्यात बाध्यता की बढ़ाई गई अवधि यदि कोई हो, सहित कुल निर्यात बाध्यता अवधि के अंतर्गत उन्हीं उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में आयातक द्वारा प्राप्त निर्यात के औसत स्तर के अलावा होगी। ऐसी औसत उन्हीं उत्पादों के लिए विगत 3 वर्षों में निर्यात निष्पादन का गणितीय औसत होगा।

यह प्रावधान है कि निर्यात बाध्यताके 50 प्रतिशत को आयातक अथवा ई पी सी जी प्राधिकार वाले ग्रुप कम्पनी/ प्रबंधित होटल द्वारा उत्पादित अन्य माल अथवा प्रदान की गई सेवा के निर्यात द्वारा भी पूरा किया जा सकता है, परन्तु इस शर्त के अधीन कि ऐसे मामलों में लगाई गई अतिरिक्त निर्यात बाध्यता पिछले तीन वर्षों में आयातक अथवा उसके ग्रुप कम्पनी/प्रबंधित होटल द्वारा प्राप्त औसत निर्यात के अलावा होगी :

यह भी प्रावधान है कि हस्तशिल्प, हैंडलूम, कुटीर, छोटे क्षेत्र, कृषि, पशु पालन, पुष्पकृषि, बागबानी, मत्स्यपालन, द्राक्ष-कृषि, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आम सेवा प्रदाता या विनिर्दिष्ट प्रयोक्ता द्वारा निर्यात का औसत स्तर बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा:

यह भी प्रावधान है कि एक्वा-कल्चर (फिशरीज सहित) से संबंधित माल के निर्यात के मामले में आयातक द्वारा निर्यात का औसत स्तर इस शर्त के अधीन बनाए रखना अपेक्षित नहीं होगा कि फिशिंग ट्रांसर्स, नौकाओं, पोतों एवं अन्य ऐसे मदों को छोड़कर अन्य माल के संदर्भ में ईपीसीजी प्राधिकार प्राप्त कर लिया गया है:

यह भी प्रावधान है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत आयातित औजारों को छोड़कर, माल को आयात की तिथि से पाँच वर्षों की अवधि के लिए अंतरित करने की अनुमति नहीं होगी, उन मामलों में भी नहीं जहाँ निर्यात बाध्यता पूरी कर ली गई हो। तथापि, पूंजीगत माल को निर्यात बाध्यता पूरी करने के बाद परन्तु आयात की तिथि से पाँच वर्षों के अंदर क्षेत्रीय प्राधिकारी और क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारी को सूचना देते हुए ग्रुप कम्पनियों के बीच अंतरित करने की अनुमति होगी:

यह भी प्रावधान है कि पुराने यू एस एस आर अथवा दिनांक 31.3.08 तक डीजीएफटी द्वारा अधिसूचित देशों को किए गए निर्यात को निर्यात के औसत स्तर निर्धारित करने के लिए गिना नहीं जाएगा:

यह भी प्रावधान है कि केवल ऐसे शिपिंग बिलों के समक्ष निर्यात को निर्यात बाध्यता पूरा करने के लिए गिना जाएगा, जिन पर ई पी सी जी प्राधिकार सं. और तिथि का उल्लेख होगा;

यह भी प्रावधान है कि इस अधिसूचना के अंतर्गत जारी प्राधिकार के समक्ष संगणित निर्यात को अन्य ई पी सी जी प्राधिकारों के समक्ष विनिर्दिष्ट निर्यात बाध्यता पूरा करने के लिए नहीं गिना जाएगा;

(2) को वास्तविक निर्यात के जरिए पूरा किया जाएगा और निर्यात प्राप्ति को आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल किया जाएगा । तथापि निम्नलिखित संवर्गों की आपूर्तियों को निर्यात बाध्यता पूरी करने के लिए गिना जाएगा:

(क) मानद निर्यात, नामतः

(i) अग्रिम प्राधिकारी/ वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम प्राधिकार/डी एफ आई ए के लिए अग्रिम प्राधिकार के संबंध में माल की आपूर्ति;

(ii) ई ओ यू अथवा एस टी पी अथवा ई एच टी पी अथवा बी टी पी को माल की आपूर्ति;

(iii) आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली (आई सी बी) के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तपोषित परियोजनाओं को माल की आपूर्ति, जहाँ विधिक करारों में सीमा शुल्क को शामिल किए बिना निविदा मूल्यांकन का प्रावधान है; आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा आई सी बी के अंतर्गत अधिसूचित बहुपक्षीय अथवा द्विपक्षीय एजेंसियों/कोषों द्वारा उन एजेंसियों/कोषों की प्रक्रियाओं के अनुसार वित्तपोषित परियोजनाओं के लिए माल और उपस्करों (प्रमुख ठेकों की एकमात्र जिम्मेदारी) की आपूर्ति तथा उन्हें लगाना जहां बोलियाँ विदेश में उत्पादित माल के लिए डेलीवरी ड्यूटी पेड (डी डी पी) कीमतों के आधार पर आमंत्रित कर मूल्यांकन किया गया जाता हो;

(iv) किसी भी ऐसी परियोजना अथवा उद्देश्य के लिए माल की आपूर्ति जिनके संबंध में वित्त मंत्रालय अधिसूचना द्वारा शून्य सीमा शुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति प्रदान करता है और आपूर्ति आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत की जाती है;

(v) आई सी बी प्रक्रिया के अंतर्गत उपर्युक्त (iv) में शामिल नहीं की गई उर्जा परियोजनाओं और रिफाइनरियों को माल की आपूर्ति;

(vi) आई सी बी के प्रतिकूल प्रतियोगी बोलियों के माध्यम से न्यूक्लियर उर्जा परियोजनाओं को माल की आपूर्ति;

(ख) घरेलू टैरिफ क्षेत्र को आई टी ए-1 मदों की आपूर्ति बशर्ते कि सरल विदेशी विनिमय वाली मुद्रा में वसूली हो;

(ग) आसानी से परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान एवं आर एंड डी सेवाओं के लिए प्राप्त विदेशी विनिमय; और

(घ) विदेशी व्यापार नीति के अध्याय 9 के दृष्टिकोण से पोर्ट हैंडलिंग सेवाओं के लिए रूपए में प्राप्त भुगतान ।

(4) "विदेश व्यापार नीति" का अर्थ है भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ii, खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. 1/2009-2014, दिनांक 27 अगस्त, 2009;



(5) "लाइसेंसिंग प्राधिकारी अथवा क्षेत्रीय प्राधिकारी" का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 6 के अंतर्गत नियुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक अथवा उक्त अधिनियम के अंतर्गत लाइसेंस अथवा प्राधिकार प्रदान करने के लिए उनके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी;

(6) "विनिर्माण" का वही अर्थ है जो केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा (2) के खंड (च) में परिभाषित किया गया है।

(7) "निर्यात उत्कृष्टता के कस्बे (टीईई)" का अर्थ कोई ऐसा चुनिंदा कस्बा है, जो निर्यात में वृद्धि की संभावना के आधार पर 750 करोड़ रुपये अथवा अधिक के माल का उत्पादन करता हो। फिर भी, हथकरघा, हस्तशिल्प, कृषि और मत्स्यपालन क्षेत्र में टीईई के लिए यह सीमा 150 करोड़ रुपये होगी।

#### सारणी

क्र.सं.	माल का विवरण
(1)	(2)
1.	सेकेंड हैंड पूंजीगत माल सहित उत्पादन पूर्व, उत्पादन और उत्पादन के पश्चात् पूंजीगत माल।
2.	आयातक द्वारा पूंजीगत माल के रूप में एसेम्बल करने के लिए एस केडी/सी केडी में पूंजीगत माल।
3.	ऐसे आयातित, एसेम्बल्ड अथवा उत्पादित पूंजीगत माल के रख-रखाव के लिए वास्तव में आयातित और अपेक्षित क्रम.सं.1 और 2 में विनिर्दिष्ट माल के सीआईएफ मूल्य के 10% तक मूल्य के खुले पुर्जे।
4.	प्राधिकार धारी के वर्तमान संयंत्र और मशीनरी के बुक मूल्य के 10% तक सीआईएफ मूल्य के खुले पुर्जे।

[फा. सं. 605/58/2009-डी बी के]

राजेश कुमार अग्रवाल, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE****(Department of Revenue)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th September, 2009

**No. 101/2009-CUSTOMS**

**G.S.R. 667(E).**— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts goods specified in the Table annexed hereto, from,-

(i) the whole of the duty of customs leviable thereon under the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), and

(ii) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the said Customs Tariff Act, when specifically claimed by the importer.

2. The exemption under this notification shall be subject to the following conditions, namely :-

(1) that the goods are imported for export of engineering and electronic products, basic chemicals and pharmaceuticals, apparels and textiles, plastics, handicrafts, chemicals and allied products and leather & leather products and are other than those required for export of products covered under following chapters/headings of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), namely:-

Chapters 1 to 4,5(other than handicrafts), 6 to 24,25 to 27, 31,40,43,44(other than handicrafts),45,47 to 49,68(other than handicrafts),69 . 70,71,81 (metals in primary and intermediate forms only),69,93,97(other than handicrafts),98; headings 7201 to 7212, 7218 to 7220,7224 to 7226,7401 to 7405, 7501 to 7504, 7601 to 7603, 7801 to 7802, 7901 to 7903, 8001 to 8002 and 8401.

(2) that the goods imported are covered by a valid authorization issued under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) Scheme to Common Service Providers(hereinafter referred to as CSP) designated by the Director General Of Foreign Trade (hereinafter referred to as DGFT), Department of Commerce(hereinafter referred to as DOC) or State Industrial Infrastructural Corporation in Towns Of Export Excellence (hereinafter referred to as TEE) in terms of Chapter 5 of the Foreign Trade Policy permitting import of goods at zero customs duty and the said authorization is produced for debit by the proper officer of customs at the time of clearance.

Provided that for import of spare parts specified at Sr.No.4 of the said Table, the validity period of the authorization shall be deemed to be the period permitted for fulfilment of the export obligation in full :

(3) that the authorization issued under the scheme shall have the details of the users of the said capital goods and the quantum of the Export Obligation(hereinafter referred to as EO) which each user would fulfil.

(4) that the Common Service provider or any of the specific users is not currently availing any benefits under Technology Upgradation Fund Scheme (TUFS) administered by Ministry of Textiles, Government of India.

(5) that the Common Service provider or any of the specific users does not avail, in the year of import of the goods, the benefit of Status Holder Incentive Scheme under Para 3.16 of the Foreign Trade Policy.

(6) that the goods imported shall not be disposed of or transferred by sale or lease or any other manner till export obligation is complete.

(7) that the Common Service provider and each of the specific users shall execute a bond in such form and for such sum as may be specified by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs and a bank guarantee equivalent to their portion of duty foregone in terms of export obligation apportioned in the authorization binding themselves to fulfil export obligation on FOB basis equivalent to six times the duty saved on the goods imported as may be specified on the licence or authorization, or for such higher sum as may be fixed or endorsed by the Licensing Authority or Regional Authority in terms of Para 5.10 of the Handbook of Procedures Vol I, issued under para 2.4 of the Foreign Trade Policy within a period of six years from the date of issue of licence or authorization, in the following proportions, namely :-

S.No.	Period from the date of issue of Authorization	Proportion of total export obligation
(1)	(2)	(3)
1.	Block of 1 <sup>st</sup> to 4 <sup>th</sup> year	50%
2.	Block of 5 <sup>th</sup> to 6 <sup>th</sup> year	50%

Provided further that where a sick unit is notified by the Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) or where a rehabilitation scheme is announced by the concerned State Government in respect of sick unit for its revival, the export obligation may be fulfilled within time period allowed by the Licensing Authority or Regional Authority as per the rehabilitation package prepared by the operating agency and approved by BIFR or rehabilitation department of State Government. In cases where the time period is not specified in the rehabilitation package, the export obligation may be fulfilled within the time period allowed by the Licensing Authority or Regional Authority which shall not exceed twelve years.

Provided also that spares (including refurbished/reconditioned spares), moulds, dies, jigs, fixtures, tools, refractory for initial lining and catalyst for initial charge, for the existing plant and machinery (imported earlier, under EPCG or otherwise), shall be allowed to be imported under the EPCG scheme subject to an export obligation equivalent to 50% of the normal export obligation prescribed above, to be fulfilled in 6 years reckoned from the date of issue of the Authorization, subject to the condition that the CIF value of import of the above spares etc. will be limited to 10% of the CIF value of the plant and machinery imported under the EPCG authorization or 10% of the book value of the plant and machinery imported earlier otherwise than under EPCG Scheme, as the case may be.

Provided also that export obligation of a particular block may be set off against the excess exports made in the said preceding block(s);

(8) that if the Authorization Holder does not claim exemption from the additional duty leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, the additional duty so paid by him shall not be taken for computation of the net duty saved for the purpose of fixation of export obligation provided the Cenvat credit of additional duty paid has not been taken;

(9) that the Authorization Holder and the other specific users produce within 30 days from the expiry of each block from the date of issue of authorization or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs may allow, evidence to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs showing the extent of export obligation fulfilled, and where the export obligation of any particular block is not fulfilled in terms of the preceding condition, the importer shall within three months from the expiry of

the said block pay duties of customs equal to an amount which bears the same proportion to the duties leviable on the goods, but for the exemption contained herein, which the unfulfilled portion of the export obligation bears to the total export obligation, together with interest at the rate of 15% per annum from the date of clearance of the goods;

(10) where the Authorization Holder fulfills 75% or more of the export obligation as specified in condition (7) (over and above 100% of the average export obligation) within half of the period specified for export obligation as mentioned in condition (7), his balance export obligation shall be condoned and he shall be treated to have fulfilled the entire export obligation;

(11) that the capital goods imported, assembled or manufactured are installed in the Common Service Provider's factory or premises and a certificate from the jurisdictional Deputy Commissioner of Central Excise or Assistant Commissioner of Central Excise, as the case may be, is produced confirming installation and use of capital goods in the Common Service Provider's factory or premises, within six months from the date of completion of imports or within such extended period as the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, may allow :

Provided that in case of import of spares, the installation certificate shall be produced within three years from the date of import :

Provided further that if the importer is not registered with central excise, he may produce the said certificate of installation and usage issued by an independent Chartered Engineer :

(12) that the imports and exports are undertaken through sea ports at Bedi (including Rozi-Jamnagar), Chennai, Cochin, Dahej, Dharamtar, Haldia (Haldia Dock complex of Kolkata port) Kakinada, Kandla, Kolkata, Krishnapatnam, Magdalla, Mangalore, Marmagoa, Muldwarka, Mumbai, Mundhra, Nagapattinani, Nhava Sheva, Okha, Paradeep, Pipavav, Porbander, Sikka, Tuticorin, Visaknapatnam and Vadinar or through any of the airports at Ahmedabad, Bangalore, Bhubaneswar, Chennai, Cochin, Coimbatore, Dabolim (Goa), Delhi, Hyderabad, Indore, Jaipur, Kolkata, Lucknow (Amausi), Mumbai, Nagpur, Rajasansi (Amritsar), Srinagar, Trivandrum and Varanasi or through any of the Inland Container Depots at Agra, Ahmedabad, Anaparthi (Andhra Pradesh), Babarpur, Bangalore, Bhadohi, Bhatinda, Bhilwara, Bhiwadi, Bhusawal, Chheharata (Amritsar), Coimbatore, Dadri, Dappar (Dera Bassi), Daulatabad (Wanjarwadi and Maliwada), Delhi, Dighi (Pune), Durgapur (Export Promotion Industrial Park), Faridabad, Garhi Harsaru, Gauhati, Guntur, Hyderabad, Jaipur, Jalandhar, Jamshedpur, Jodhpur, Kanpur, Karur, Kota, Kundli, Loni (District Ghaziabad), Ludhiana, Madurai, Malanpur, Mandideep (District Raisen), Miraj, Moradabad, Nagpur, Nasik, Pimpri (Pune), Pitampur (Indore), Pondicherry, Raipur, Rewari, Rudrapur (Nainital), Salem, Singanalur, Surat, Surajpur, Tirupur, Tuticorin, Udaipur, Vadodara, Varanasi, Waluj (Aurangabad) or through the Land Customs Station at Agartala, Amritsar Rail Cargo, Attari Road, Changrabandha, Dawki, Ghojadanga, Hilli, Jogbani, Mahadipur, Nepalganj Road, Nautanva (Sonauli), Petrapole, Ranaghat, Raxaul, Singhabad and Sutarkhandi or a Special Economic Zone notified under section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005):

Provided that the Commissioner of Customs may, by special order or a public notice and subject to such conditions as may be specified by him, permit import and export through any other sea-port, airport, inland container depot or through a land customs station within his jurisdiction.

(13) notwithstanding anything contained in condition (9) above, where the Licensing Authority or Regional Authority grants extension of block-wise period for any block(s) or overall period of fulfilment of export obligation upto a period of two years or regularization of shortfall in export obligation, not exceeding five percent of such export obligation, the said block-wise period or overall period of export obligation shall be extended or condoned by the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be :

Provided that in respect of sick units referred to in the first proviso to condition (7) extension of overall period of export obligation shall not be allowed :

Provided further that the Export Obligation period shall not be extended beyond 12 years including the original Export Obligation period of 6 years .

3. Where the goods specified in the said Table are found defective or unfit for use, the said goods may be re-exported back to the foreign supplier within three years from the date of payment of duty on the importation thereof:

Provided that at the time of re-export, the goods are identified to the satisfaction of the Deputy Commissioner of Customs or Assistant Commissioner of Customs, as the case may be, to be the same as the goods which were imported.

4. This notification, for import of goods specified at Serial Nos.1 and 2 of the said table, shall have effect upto 31<sup>st</sup> December, 2011.

Explanation – For the purpose of this notification,-

1. "Capital goods" has the same meaning as assigned to it in Paragraph of 9.12 of the Foreign Trade Policy;

2. "Common Service Provider (CSP)" means a service provider who is designated or certified as a Common Service Provider by the DGFT, Department of Commerce or State Industrial Infrastructural Corporation in a Town of Export Excellence.

3. "Export obligation", -

(1) means obligation on the Common Service provider and each of the specific users to export to a place outside India, goods manufactured or capable of being manufactured or services rendered by the use of capital goods imported in terms of this notification. The export obligation shall be over and above the average level of exports achieved by the Common Service provider or the specific user in the preceding three licensing years for the same and similar products within the overall export obligation period including the extended period, if any. Such average shall be the arithmetic mean of export performance in the last 3 years for the same and similar products.

Provided that upto 50% of the export obligation may also be fulfilled by export of other good(s) manufactured or service(s) provided by the Common Service provider or the specific user or his group company or managed hotel, which has the EPCG authorization subject to the condition that in such cases, additional export obligation imposed shall be over and above the average exports achieved by the Common Service provider or the specific user or his group company or managed hotel in preceding three years for both the original and the substitute product(s) or service(s) :

Provided further that in case of export of goods relating to handicraft, handlooms, cottage, tiny sector, agriculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture, the Common Service provider or the specific user shall not be required to maintain the average level of exports :

Provided further that in case of export of goods relating to aquaculture(including fisheries), the Common Service provider or the specific user shall not be required to maintain the average level of exports subject to the condition that EPCG authorization has been obtained for goods other than fishing trawlers, boats, ships and other similar items.

Provided also that the goods, excepting tools, imported under this notification by the aforesaid sectors, shall not be allowed to be transferred for a period of five years from the date of imports even in cases where export obligation has been fulfilled. Transfer of capital goods would, however, be permitted within the group companies, after fulfillment of export obligation but before five years from the date of imports, under intimation to Regional Authority and jurisdictional Central Excise Authority :

Provided also that exports made to former USSR, or to such countries as notified by Director General of Foreign Trade as on 31.3.08, shall not be counted for fixing the average level of exports :

3330 G1109-4

Provided also that exports against only such shipping bills which mention the EPCG authorization No. and date shall be counted for the discharge of the export obligation;

Provided also that exports counted against the authorization issued under this notification shall not be counted towards fulfilment of other specific Export Obligations against other EPCG authorizations;

(2) shall be fulfilled through physical exports and the export proceeds shall be realized in freely convertible currency. However, the following categories of supplies, shall also be counted towards fulfillment of export obligation:

(a) deemed exports, namely:

(i) supply of goods against Advance Authorization/Advance Authorization for Annual Requirement/ Duty Free Import Authorization (DFIA);

(ii) supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronics Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio-Technology Parks (BTPs);

(iii) supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by Department of Economic Affairs (DEA), Ministry of Finance (MOF) under International Competitive Bidding (ICB) in accordance with procedures of those agencies or Funds, where legal agreements provide for tender evaluation without including customs duty; supply and installation of goods and equipments (single responsibility of turnkey contracts) to projects financed by multilateral or bilateral agencies or Funds as notified by DEA, MOF under ICB, in accordance with procedures of those agencies/Funds, where bids may have been invited and evaluated on the basis of Delivery Duty Paid (DDP) prices for goods manufactured abroad;

(iv) supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits import of such goods at zero customs duty and the supply is made under ICB procedure;

(v) supply of goods to power projects and refineries not covered in (iv) above under ICB procedure;

(vi) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to ICB;

(b) Supply of ITA-1 items to Domestic Tariff Area, provided realization is in free foreign exchange;

(c) Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for Research and Development (R&D) services; and

(d) Payments received in rupee terms for port handling services in terms of chapter 9 of the Foreign Trade Policy.

4. "Foreign Trade Policy" means the Foreign Trade Policy 2009-2014 published in the gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii) vide notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry, No.1/2009-2014 dated the 27<sup>th</sup> August, 2009 as amended from time to time;

5. "Licensing Authority or Regional Authority" means the Director General of Foreign Trade appointed under section 6 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) or an officer authorized by him to grant an authorization under the said Act;

6. "Manufacture" has the same meaning as defined in clause (f) of section 2 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944).

7. "Towns of Export Excellence(TEE)" means a selected town producing goods of Rs.750 Crores or more based on potential for growth in exports. However for TEE in Handloom, Handicraft, Agriculture and fisheries sector the threshold limit would be Rs.150 Crores.

Table

S.No.	Description of goods
(1)	(2)
1.	Capital goods for pre-production, production and post production including second hand capital goods.
2.	Capital goods in Semi Knocked Down (SKD) / Completely Knocked Down (CKD) conditions to be assembled into capital goods by the importer.
3.	Spare parts of CIF value upto 10% of the CIF value of goods specified at Serial Nos.1 and 2 as actually imported and required for maintenance of capital goods so imported, assembled, or manufactured.
4.	Spare parts of CIF value upto 10% of the book value of the existing plant and machinery of the authorization holder.

[F. No. 605/58/2009-DBK]

RAJESH KUMAR AGARWAL, Under Secy.